REFERENCE TO THE OPENING OF THE CLOSED INDUSTRIAL UNITS OF THE DALMIA-JAIN GROUP IN DERHI-ON-SONE AREA IN BIHAR

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : महोदया, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत आवश्यक समस्या की तरफ खींचना चाहता हूं । महोदया, बिहार राज्य में डेहरी-आन-सोन एक छोटा सा शहर है और वहां पर डालमियां जैन के बहुत से उद्योग लगे हुए हैं । मान्यवर, डालमियां जैन एक ऐसा कंसर्न है, जो इस देश के मजदूरों को चूसने में सबसे आगे रहा है । अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले, छह महीने पहले इस उद्योग के प्रबंधकों ने सारे उद्योग धंधे बंद कर दिए । आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन उद्योग-धंधों में 22 हजार से अधिक मजदूर काम करते है । आज छह महीने से यह सारे मजदूर बेकार बैठे हैं....

एक माननीय सदस्य : दो-तीन साल से बेकार हैं.....

श्री रामानन्द यादव : नहीं—नही, छह महीने से कुछ अधिक दिनों से वहां यह 22 हजार मजदूर बेकार बैठे हैं । उनको तनख्वाह नहीं मिलती, उनके सामने भुखमरी की समस्या आ गई है, वे बीमार पड़ गए है, उनके बच्चों की पढ़ाई छूट गई है । डालमियां नगर के प्रबंधकों के इशारों पर वहां की म्युनिसपेल्टी ने पानी का कनेक्शन, जहां उनके आवास थे, वह काट दिए हैं, बिजली का कनेक्शन काट दिया है और आज स्थिति यह हो गई है कि वे मजदूर भीख मांग कर, कर्ज लेकर अपना पोषण कर रहे हैं । मजदूरों के प्रतिनिधियों ने बिहार सरकार से अनेकों बार मिलकर यह दबाव डालने की कोशिश की कि सरकार जल्दी से जल्दी मिल-प्रबंधकों पर प्रभाव डालकर के इन उद्योग-धंधों को खुलवाए । उधर उल्टे प्रबंधक चाहते थे कि सरकार उनकी बात माने । महोदया, आप जानकर ताज्जुब करेंगी कि करोड़ों रुपए बिहार सरकार के और भारत सरकार के कर्जे या कर के रूप में इस डालमियां उद्योग पर बाकी है । उन बकाया को यह प्रबंधक चाहते थे कि सरकार माफ कर दे, तब वह मिलों को चलाएं । लेकिन सरकार इस प्रकार की कार्यवाही के लिए तैयार नहीं थी । मिल के मजदूरों के प्रतिनिधियों ने भारत सरकार के यहां भी एक प्रतिनिधि-मंडल भेजा था और आग्रह किया था कि जल्द से जल्द मिल को खुलवाया जाए ।

महोदया, आप यह भी जानकर ताज्जुब करेंगी कि इलेक्शन के पहले डालमियां जैन के जो प्रबंधक हैं, उनकी तीन शुगर मिलें हैं, बिहार राज्य में । एक है विस्वान शुगर फैक्ट्री सीवान में, एक है हथुआ में हथुआ शुगर फैक्ट्री और एक लौरिया में चम्पारन में—इन तीनों को बन्द कर दिया । आप को सुनकर ताज्जुब होगा कि करीब चार करोड़ रुपया किसानों का केन का बकाया है इनके ऊपर । ठीक इलेक्शन के पहले बन्द कर दिया इसलिए कि सरकार इस को टेक-ओवर न कर सके । आज किसानों का गन्ना खड़ा है, सूखने की नौबत आ गई है । महोदया, मैं आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द वह तीन कदम उठाये:

सरकार जिस तरह से हो सके प्रबन्धकों पर दबाव डाल कर उद्योग धन्धों को खुलवा दे, अगर इस में सरकार असमर्थ है तो भारत सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द डालमिया जैन के जो अधिकारी हैं उनको कैद कर दे क्योंकि उस आदमी को कोई हक नहीं है आजाद रहने का जिस के ऊपर मजदूरों की तनख्वाह का करोड़ों रुपये बकाया है । मजदूरों ने स्ट्राइक नहीं की, मालिकों ने अपनी ओर से बन्द कर दिया । दोषी वह हैं, उनको एरेस्ट करिए । तीसरा कदम यह उठाइये कि इन मिलों को टेक-ओवर कर लें और खुलवा दें । चौथा मेरा सजेशन यह है कि मजदूर बेकार हैं उनको रिलीफ दिया जाए । वह बीमारी से ग्रस्त हैं, देहातों में घूम घूम कर भीख मांग रहे हैं । उनका पानी का कनेक्शन रेस्टोर किया जाय, बिजली का कनेक्शन रेस्टोर किया जाय । बच्चें जो पढ़ते हैं उनकी फीस माफ की जाय । सरकार को जल्द से जल्द उनकी रिलीफ का काम शुरू करना चाहिए ।

जहां तक शुगर मिल्स का सवाल है मैं आप से आग्रह करूंगा कि सरकार;

भी अपनी तरफ से थोड़ा दबाव डाले ताकि किसानों का जो बकाया पैसा है केन का वह चुकता हो सके । मिलों मे जो चीनी पड़ी हुई है उसको बेच कर सरकार किसानों का पैसा चुकता कर दे । मेरा अपना ख्याल है कि दो-तीन करोड़ रुपये की चीनी पड़ी होगी । जो शुगर अंडरटेकिंग एक्ट है उस के तहत सरकार इन मिलों का भी अधिग्रहण कर ले । आज बात यह है कि जब तक भारत सरकार कोई स्ट्राँग एक्शन नही लेगी डालमियाँ जैन के प्रबन्ध कुछ सुनेंगे नही वह चाहते हैं कि भारत सरकार और प्रान्तीय सरकार से कुछ कन्सेशन ले लें, लेकिन मैं समझता हूं कि किसी तरह का कन्सेशन इस कन्सर्न को देने की जरूरत नहीं है । बराबर यह एन्टी-नेशनल काम करता है, मजदूरों के, किसानों के हक के खिलाफ काम करता है, सरेआम ब्लेक करता है, सारा डालडा ब्लेक मार्केट में जाता है, और दूसरी चीज़ें भी हैं । इसलिए मैं आप से चाहूंगा कि सरकार दबाव डालकर..

उपसभापति : डालडा डालमिया बनाते है ?

श्री रामानन्द यादव : डालमिया जैन कन्सर्न है । सरकार इन मिलों को खुलवाए और किसानों का पैसा दिलवाये ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार): यह तो बोलकर बैठ गये । आप सरकार से भी जवाब दिलवाइये ।

उपसभापति : जवाब बाद में आयेगा । यह कालिंग अटेंशन नहीं है, स्पेशल मेंशन है ।

REFERENCE TO THE DEATHS CAUSED BY ADULTERATION IN KERALA

SHRI K. MOHANAN (Kerala): With great pain, deep concern and strong protest I am raising this serious issue on the floor of this House, with your kind permission. For the last one month or so, the State of Kerala is experiencing the tragic incidents of kerosene distributed by Hindustan Petroleum Company, known as 'killer kerosene'. Already, 16 valuable lives have been lost and more than 100 persons have been hospitalised due to serious burn injuries. Kerosene distributed by H. P. C. in Kerala for the month of February 85' was highly inflammable than that of even petrol. Kerosene is the only source of energy for the rural population of our country. Naturally, the poor innocent people have become the victims of the tragedy.

To anybody's surprise, the State Government and the Hindustan Petroleum Company have failed to protect these poor innocent people from the fatal consequences of this 'Killer kerosene'. It has come to my notice that the kerosene distributed was mixed with naptha, a highly inflammable petroleum product. The first case was reported in the second week of February. But this tragic incident is being continued even afer one month. Nobody is interested or prepared to take the responsibility for this tragic incident. May be, the human life is the cheapest available commodity in the market;

It is very easy to find out the reason for this calamity with a simple analysis of the sample of kerosene in any common laboratory. But with pain and protest I would like to say that the authorities were never concerned for the last one month. For the last 30 or 40 days reports are appearing everyday in the press regarding the fatal incidents of 'Killer kerosene' from various parts of the State. Even then the authorities have failed to check it.

In this backgound, I would like to make a fervent appeal to the Union Government to intervene and seize the entire stock of 'Killer kerosene' distributed by the H.P.C. I also request the Government to give necessary directions to the H.P.C. to give sufficient compensation to the victims. Above all, I would urge upon the Government to institute an enquiry into this matter at top level immediately.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2 o'clock.

The House then adjourned for lunch at 22 minutes past one of the clock.